

SHRI N. GIRI PRASAD: A major bottleneck is here. The Central Government, especially the Central Water Commission, has to give the techno-economic clearance to this project, and the environmental clearance also has to be given by the Ministry of Environment. Unless these things are done and this project is taken up now to be completed at least by the end of the Ninth Plan, all the States will be affected. So, I request the Government to give top priority to this project in national interest and also in the interest of development of those areas.

Thank you.

Need to enhance postmatric scholarship

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि एक निर्धारित सीमा के ऊपर राज्य शासन को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की विभिन्न दरें दिनांक 1-7-89 से प्रभावित की गई है। इसके बाद से अब तक महंगाई एवं मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति की राशि बच्चों के लिए काफी अप्राप्त होती है। यह इतनी अप्राप्त है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 8वीं से 10वीं कक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति की दर निर्धारित की गई है, उससे भी कम छात्रवृत्ति 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को केन्द्रीय शासन द्वारा दी जाती है।

महोदय, जहां एक ओर राज्य शासन की तुलना में केन्द्र शासन द्वारा दी जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें कम हैं, वहीं दूसरी ओर जो छात्रवृत्ति अभी मिल रही है, वह भी आज के मूल्य सूचकांक को देखते हुए बहुत कम है और इसमें अनुसूचित-जाति, अनुसूचित - जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई-लिखाई के संसाधन जुटाना कठिन होता है। केन्द्र प्रवर्तित योजना

के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा दी जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाया जाना आवश्यक है, वही सिद्धांत रूप से छात्रवृत्ति की दरों को मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करते हुए प्रति वर्ष जुलाई माह में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व तत्समय प्रचलित मूल्य सूचकांक के अनुरूप प्रति वर्ष के लिए छात्रवृत्ति की दरों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

केन्द्र शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दी जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता हेतु पाठकों की आय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है —

- (अ) जिनकी आय पूर्व सधारण भत्ता सीमा रुपए 1500 एवं फीस प्रति माह से अधिक न हो।
- (ब) जिनकी प्रतिमाह 1. ग्रुप "ए" के आय रुपए 1500 लिए पूर्ण विवरण से अधिक हो किंतु भत्ता तथा फीस रुपए 2.00 प्रति माह से अधिक न हों।
2. अन्य ग्रुपों के लिए आधार सधारण भत्ता तथा पूर्ण फीस

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रुपए 2,000 प्रति माह से अधिक आय वाले पालकों/माता-पिता के बच्चों को केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता नहीं है। यह आय सीमा अत्यंत अव्यावहारिक है एवं वर्तमान वेतनमानों के आधार पर यदि किसी परिवार में एक से अधिक व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी की भी सेवा में हैं तो उनके बच्चे केन्द्रीय वेतनमानों की पात्रता नहीं रखेंगे। कई चतुर्थ श्रेणियों में भी कुल उपलब्धि रुपए 2,000 प्रति माह से अधिक होती है इस आय सीमा को पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने प्रस्ताव भेजा है कि आय सीमा को बढ़ाया जाए और उसे मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए।

अतः मैं आपके माध्यम से माग करता हूं कि केन्द्रीय शासन से जो केन्द्रीय प्रवर्तित

योजना के अंतर्गत अनुसूचित-जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को जो पोस्ट मैट्रिक छावृत्ति की राशि दी जाती है, उसकी दरों में वृद्धि की जाए और छावृत्ति का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा जो पालकों की आय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें भी वृद्धि की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Ram Gopal Yadav, absent, Shri Janardan Yadav, absent. Shri Sunder Singh Bhandari, absent. Dr. Murli Manohar

Joshi, absent. Shri Satya Prakash Malaviya, absent. Shri Mohd. Masud

Khan, absent. Maulana Obaidullah Khan Azmi, absent. Dr. Jagannath Mishra, absent. Shri Raghavji, absent. Shri Bhupinder Singh Mann, absent.

Problems faced by Wagon industry

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, the wagon industry in the country is reportedly facing an acute crisis due to lack of orders from the Ministry of Railways. Though there is a budgetary provision for the Ministry to procure 18,000 wagons during the current year, they have not done it. The Ministry of Railways is the Sole client for the wagon industry.

According to the "Hindustan Times", dated 2nd May, 1994; even the budgetary provision for the procurement of 13,000 wagons during the current year is almost 30 per cent less than the plan of 25,000 wagons during the Eighth Plan period. It has been pointed out that it is a labour intensive industry. If the present situation continues for some more time,

then, the wagon industry and most of the ancillary units both in the private sector and the public sector, will be forced to close down their units leading to the throwing out of employment of those who are directly employed and those who are working in the various ancillary units. The Ministry of Railways must take immediate action, without any further delay, to save the industry. Thank you, Sir.

Agitation by diploma Engineers in U.P.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, करप्पान को बर्लई फिनामिनन मानने वाले अपने देश में ग्रामीण विकास के नाम पर करोड़ों रुपयों की लूट पर कोई अचरज न हो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप को इस बात पर जरूर अचरज होना कि बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी और शासन, उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार की जानकारी में यह लूट हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक की 10 लाख की योजना के तहत उत्तर प्रदेश को साठे 11 लाख रुपए दिए गए। . . मान्यवर, इस साठे 11 लाख रुपए से कुओं का निर्माण होना था, एकीकृत सिंचाई और पेय जल योजना का निर्माण होना था। इसी के साथ साथ ड्रेन का भी निर्माण होना था। कुछ तारीख में आपके विचार में लाना चाहता हूँ। पहली तारीख है 17 फरवरी, 1993। 17 फरवरी 1993 को इन कामों के लिए धन आवंटित किया गया और दूसरी तारीख है 16 मार्च, 1993 जिसमें इन बच्चों के प्राक्कलन की स्वीकृति मुख्य अधिकारी ने दी और जो हिदायतें भेजी गई थीं उन में से एक हिदायत यह थी कि 31 मार्च, तक इस धन का व्यय जरूर हो जाना चाहिए। निर्माण के लिए कुल 15 दिन का समय दिया था। जाहिर है कि निर्माण हुआ नहीं और सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गया कागजों पर। . .

(उपसभापति महोदय को पीठासीन हुई)

उपसभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि साठे 11 लाख रुपए आवंटित किया